



प्रभारी

राष्ट्रपति बितरण एकक

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 350
Km 30
Distt 100
C.P.B. 220

सं. 1094]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2004/पौष 1, 1926

No. 1094]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004/PAUSA 1, 1926

पूरा किया

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2004

प्रभारी

रा० वि० एकक

का.आ. 1402(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विजेन्द्र जैन की अध्यक्षता में “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है जो इस बात का न्यायनिर्णय करेगा कि क्या असम के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोड़ोलैंड (एनडीएफबी) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं अथवा नहीं।

[फा. सं. 11011/46/2004-एनई-III]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2004

S.O. 1402(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the “Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting Justice Shri Vijender Jain, Judge of Delhi High Court for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the National Democratic Front of Boroland (NDFB) of Assam as Unlawful Association.

[F.No. 11011/46/2004-NE-III]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.